भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 338
02 दिसम्बर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कार्यान्वित योजनाओं का निष्पादन

338. डॉ. नामदेव किरसानः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए नई पहल, योजनाएँ, कार्यक्रम एवं योजनाएँ आरंभ की हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने हेतु लागू की गई योजनाओं के प्रदर्शन की समीक्षा की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार किसानों की आय को दोगुना करने में अड़चन पैदा करने वाली बाधाओं को दूर करने का है;

(घ) उक्त पहलों, योजनाओं, कार्यक्रमों एवं योजनाओं ने किसानों, विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों के जीवन की गुणवत्ता में किस हद तक सुधार किया है;

(ङ) महाराष्ट्र में असिंचित भूमि वाले किसानों के कल्याण हेतु उक्त पहलों, योजनाओं, कार्यक्रमों एवं योजनाओं को कार्यान्वित करने में केंद्र एवं राज्य सरकारों की क्या भूमिका है; और

(च) उक्त योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): भारत सरकार महाराष्ट्र सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के किसानों के कल्याण के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के साथ-साथ केन्द्र प्रायोजित योजनाओं और कार्यक्रमों की एक व्यापक श्रृंखला को कार्यान्वित कर रही है। इन योजनाओं में ऋण, बीमा, आय सहायता, इंफ्रास्ट्रचर, बागवानी सहित फसलें, बीज, यंत्रीकरण, विपणन, जैविक और प्राकृतिक खेती, किसान समूह, सिंचाई, विस्तार, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से फसलों की खरीद और डिजिटल कृषि सहित कृषि के संपूर्ण क्षेत्र को शामिल किया गया है। कृषि क्षेत्र में राज्यों को सहायता देने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की सूची **अनुबंध** में दी गई है।

(ख) से (च): भारत सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि के व्यापक विकास के लिए एक एकीकृत कार्यनीति का पालन करती है जो निम्नलिखित उद्देश्यों पर केंद्रित है:-

i. फसल उत्पादन/उत्पादकता में वृद्धि
ii. उत्पादन लागत में कमी
iii. किसानों की आय बढ़ाने के लिए उनकी उपज का लाभकारी मूल्य
iv. कृषि विविधीकरण
v. फसलोपरांत मूल्य संवर्धन का विकास
vi. सतत कृषि के लिए जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होना और फसल हानि को कम करना।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की सभी योजनाएँ/कार्यक्रम इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समन्वित हैं। सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) के बजट आवंटन को वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान में 21,933.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2025-26 के बजट अनुमान में 1,27,290.16 करोड़ रुपये कर दिया है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने 75,000 किसानों की सफलता की कहानियों का संकलन जारी किया है, जिन्होंने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग एवं संबद्ध मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं के अभिसरण से अपनी आय दो गुना से अधिक बढ़ा ली है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि वर्ष जुलाई, 2018- जून, 2019 के संदर्भ में एनएसएस के 77वें दौर (जनवरी, 2019 - दिसंबर, 2019) के दौरान कृषि परिवारों का स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) किया। इन सर्वेक्षणों के अनुसार, प्रति कृषि परिवार की अनुमानित औसत मासिक आय वर्ष 2012-13 (एनएसएस 70वें दौर) में 6,426 रूपए से बढ़कर वर्ष 2018-19 (एनएसएस 77वें दौर) में 10,218 रूपए हो गई।

घरेलू उपभोग व्यय पर एनएसएसओ सर्वेक्षण (वर्ष 2023-24) के अनुसार, अखिल भारत औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) के अनुमानों की तुलना निम्नानुसार है:

क्षेत्र	विभिन्न अवधियों में औसत एमपीसीई (रु.)	
	2011-12 एनएसएस (68वां दौर)	2023-2024
ग्रामीण	1,430	4,122
शहरी	2,630	6,996
ग्रामीण एमपीसीई का % अंतर	83.9	69.7

अनुबंध

कृषि में राज्यों को सहायता देने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की सूची

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
4. संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस)
5. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)
6. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन
7. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम)
8. नमो ड्रोन दीदी
9. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)
10. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
11. स्टार्ट-अप्स और ग्रामीण उद्यमों के लिए एग्री फंड (एग्रीश्योर)
12. पर ड्रोप मोर क्रॉप (पीडीएमसी)
13. कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)
14. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
15. सॉयल हेल्थ एंड फर्टीलिटी (एसएचएंडएफ)
16. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
17. कृषि वानिकी
18. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
19. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
20. बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी)
21. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
22. समेकित कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)
23. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
24. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-ऑयल पाम
25. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन
26. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
27. डिजिटल कृषि मिशन
28. राष्ट्रीय बांस मिशन

*****